

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4057

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का कार्यान्वयन

4057. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल कृषि मिशन की स्थिति क्या है तथा इसमें शामिल एग्रीस्टैक, किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भ वाले ग्राम मानचित्र और बोर्डेड फसल की रजिस्ट्री जैसे प्रमुख घटकों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले वर्ष डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया था और यदि हां, तो उन राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां यह सर्वेक्षण किया गया था और इस वर्ष तथा आगामी वर्षों में और किन राज्यों और जिलों को इससे जोड़ने की योजना बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि के लिए डीपीआई के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो उन प्रतिभागी राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इस वर्ष और आगामी वर्षों में डीपीआई को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है;

(घ) कितने किसान आईडी बनाए गए हैं और उन राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इन्हें कार्यान्वित किया गया है;

(ङ) आगामी तीन वर्षों में किसान आईडी तैयार करने के लिए समय-सीमा और लक्ष्य क्या हैं और इसको किन जिलों में कार्यान्वित करने की योजना है; और

(च) क्या भूमि रिकॉर्ड और अन्य किसान-संबंधी डेटा को आपस में जोड़ने में कोई विसंगतियां पाई गई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): डिजिटल कृषि मिशन में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मैप के निर्माण की परिकल्पना की गई है, ताकि देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम किया जा सके, जिससे नवीन किसान-केंद्रित डिजिटल समाधान तैयार किए जा सकें और सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके। एग्रीस्टैक में कृषि क्षेत्र की तीन आधारभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस अर्थात् किसानों की

रजिस्ट्री, जियो-रेफरेंस विलेज मैप और फसल बोर्ड गई रजिस्ट्री शामिल हैं जो सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई और रखी जाती हैं। सरकार की योजना 2026-27 तक 11 करोड़ किसान आईडी बनाने की है। 21.03.2025 तक कुल 4,58,05,017 किसान आईडी बनाए जा चुके हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के लिए भू-संदर्भित गाँव के नक्शे एक पूर्व-आवश्यक शर्त हैं और 2024 में खरीफ में 436 जिलों में DCS किया गया था। अब तक 450 से अधिक जिलों में रबी 2024 में लगभग 23 करोड़ कृषि भूखंडों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। सरकार की योजना 2025-26 में देश के सभी जिलों में DCS आयोजित करने की है। इसके अलावा, 16 अगस्त, 2024 को कृषि निर्णय प्रणाली शुरू की गई और भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) ने 130 लाख हेक्टेयर से अधिक मृदा मानचित्रों का प्रोफाइल निर्माण पूरा कर लिया है।

वर्तमान में, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विरासत और भूमि लेनदेन को शामिल करने के लिए भूमि रिकॉर्ड संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपडेट किए जाते हैं।

राष्ट्रव्यापी प्रगति: राज्य किसानों की रजिस्ट्री.

क्र. संख्या	राज्य	सृजित किसान आईडी की संख्या (21.03.2025 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	38,45,143
2.	असम	3,63,910
3.	बिहार	1,064
4.	छत्तीसगढ़	18,18,359
5.	गुजरात	40,83,036
6.	मध्य प्रदेश	69,21,210
7.	महाराष्ट्र	81,37,299
8.	ओडिशा	1,87,223
9.	राजस्थान	56,68,877
10.	तमिलनाडु	23,76,229
11.	तेलंगाना	295
12.	उत्तर प्रदेश	1,26,22,458

राष्ट्रव्यापी प्रगति: डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की स्थिति

#	राज्य का नाम	जिलों में डीसीएस शुरू किया गया	भूखंड का सर्वेक्षण किया गया (21.03.2025 तक)
1.	बिहार	28	45,49,390
2.	गुजरात	33	39,31,504
3.	महाराष्ट्र	34	67,38,157
4.	ओडिशा	30	1,77,23,859
5.	राजस्थान	30	4,50,52,135
6.	उत्तर प्रदेश	75	5,23,27,196
7.	आंध्र प्रदेश	26	90,00,000
8.	मध्य प्रदेश	55	4,63,00,000
9.	तमिलनाडु	38	3,84,45,754
10.	केरल	03	8,17,100
11.	असम	27	27,30,397
12.	झारखंड	5	1,36,368
13.	तेलंगाना	32	36,81,902
14.	छत्तीसगढ़	19*	2,68,672
15.	पंजाब	23	17,707
16.	उत्तराखंड	03	1,062
